persons and the targetted exports during the first five years would be Rs. 264 crores.

अनधिकृत रूप से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वाले व्यक्ति

305. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग 4,000 से भी अधिक लोक अनधिकृत रूप से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देना बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी राशि की बचत होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अनधिकृत लोगों द्वारा अब तक प्राप्त की गयी पेंशन की राशि वापस वसूल कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक वापस वसूल की गयी कुल राशि कितनी है और इन लोगों ने अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त की थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन केवल केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई संस्वीकृति पर ही आहरित की जा सकती है। तथापि, 4000 से अधिक मामलों में पेंशन स्थगित/निरस्त बनी रही क्योंकि यह पाया गया था कि इन मामलों में पेंशन, झूठी सूचना प्रस्तुत करके और/अथवा जाली दस्तावेज पेश करके प्राप्त की गई थी।

(ग) चूंकि पेंशन, इस योजना की शुरुआत से ही स्थगित/निरस्त की गई है इसलिए इस खाते में संभावित बचत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) जहां कहीं भी वैयक्तिक मामलों में जरूरी हुआ, वहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के माध्यम से वसूली के आदेश दिए जाते हैं। तथापि, अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

Favouritism in granting of Licences for Pilot Projects

306. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in Indian Express on 11th July, 1995 captioned "DOT may seek directive from Cabinet Panel on US West"

(b) whether telecom employees unions are demanding cancellation of letter of intent issued to US West;

(c) whether it is a fact that several multinationals have not participated in the cellulars and basic services tendering competitions due to favouritism shown to US West and

(d) if so, what is the reaction of Government thereto and recommendation made by the committee of Officers. Department of Telecommunications formed in 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) National Federation of Telecom Employees has filed a case in Madras High Court demanding cancellation of the Letter of Intent to M/s US West in Tamilnadu Circle.

(c) No such information/representations have been received so far.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

Inquiry into the Death of Rajan Pillai

307. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any inquiry has been conducted to probe the circumstances which led to the death of Rajan Pillai in custody; and

(b) if so, the details and the outcome thereof?